



## प्रगति (PRAGATI) – सक्रयिता से शासन और समय पर कार्यान्वयन

### स्रोत: PIB

प्रधानमंत्री ने प्रगति (PRAGATI) – सक्रयिता से शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- **प्रगति (PRAGATI):** यह एक अभिनव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम मंच है, जिससे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चिति तथा जनता की शिकायतों का निवारण करना है।
  - यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है, “टीम इंडिया” दृष्टिकोण को प्रोत्साहित तथा लालफीताशाही से बचते हुए अंतरराज्यीय विवादों का कुशलतापूर्वक समाधान करता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** प्रगति (PRAGATI) एक तीन-स्तरीय तंत्र पर आधारित है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं। प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत नरिणय समयबद्ध तरीके से लिये जाते हैं और अड़चनों का त्वरित निवारण सुनिश्चिति होता है।
  - यह प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भू-स्थानिक मानचित्रण (Geo-spatial mapping), ड्रोन फीड और केंद्रीकृत डेटा प्रणाली जैसी तकनीकों का समन्वय करता है।
  - यह प्रणाली केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS), पीएम गतिशक्ति, पर्यावरण मंजूरी एवं अनुपालन पोर्टल (PARIVESH) और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल के साथ एकीकृत है, जिससे वास्तविक समय पर निगरानी और पूर्वानुमान आधारित ट्रैकिंग संभव होती है।
- **प्रभाव:** वर्ष 2024 तक, प्रगति (PRAGATI) मंच ने 205 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की 340 से अधिक महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने में मदद की है।
  - जल जीवन मशिन, स्वच्छ भारत अभियान और सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन में सुधार किया गया, जिससे सीधे करोड़ों नागरिकों को लाभ मिला।
  - करमचारी भवषिय नधि (EPF) भुगतान, आयकर रफिंड और अन्य सार्वजनिक शिकायतों जैसी नागरिक समस्याओं का समाधान किया गया, साथ ही प्रणालीगत तंत्र में सुधार कर पुनरावृत्त को रोकने की दशा में कदम उठाए गए।

## PRAGATI की मुख्य विशेषताएं

- भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करता है।
- राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी चिंताओं को सुना जाए।
- परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाता है और जवाबदेही में सुधार करता है।
- फॉलो-अप और निरंतर समीक्षा के लिए निर्णयों को बनाए रखने की अंतर्निहित सुविधा।
- विभिन्न हितधारकों के बीच वास्तविक समय में सहयोग और सूचना साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- PMO के कार्यालय को कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को हल करने और परियोजना पूर्णता में तेजी लाने में सक्षम बनाता है।
- सरकारी निकायों में अंतर-निर्भरता के कारण परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं से निपटता है।
- PMO, भारत सरकार के सचिव और राज्य मुख्य सचिवों को शामिल करते हुए तीन-स्तरीय IT आधारित प्रणाली के साथ संचालित होता है।

प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (PRAGATI)

और पढ़ें... [PRAGATI \(प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन\)](https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pragati-proactive-governance-and-timely-implementation)